भाग-1

A केन्द्र सरकार की योजनाएँ

1 प्रधानमंत्री जन-धन योजना

- इस योजना का आदर्श वाक्य 'मेरा खाता भाग्य विधाता' है।
- राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन दो चरणों में कार्यान्वित की जा रही है।
  प्रथम चरण : **15 अगस्त, 2014 से 14 अगस्त, 2015 तक**
  द्वितीय चरण : **15 अगस्त, 2015 से 14 अगस्त, 2018 तक**
- इसके अलावा 6 माह तक खाते के संतोषजनक संचालन के बाद आधार से जुड़े खातों को 5000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा।
- भारत सरकार को प्राप्त गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण-पत्र में स्पष्ट उल्लिखित है कि वित्तीय समावेशन अभियान के तहत **एक सप्ताह में सर्वाधिक 18096130 बैंक खाते** खोलने की उपलब्धि वित्तीय सेवाएं विभाग को प्राप्त है।

2 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

- बीमा राशि **रु. 2 लाख**, जो किसी भी कारण से मृत्यु होने की स्थिति में देय होगी।
- बीमा अवधि एक वर्ष (**1 जून से 31 मई**) हर वर्ष **31 मई** तक नवीकरण कराना होगा।
- **18 से 50** वर्ष की आयु वर्ग के सभी बैंक खाताधारक इस योजना के लिए पात्र।
- सालाना प्रीमियम **राशि रु. 330**।
- सदस्यता की **अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष**, एक बार सदस्य बनने के बाद **55 वर्ष** की उम्र तक ले सकते हैं लाभ।
- 55 वर्ष की उम्र पूरी होने या बैंक खाता बंद होने या इसमें अपर्याप्त राशि होने पर **समाप्त हो जाएगी सदस्यता**।

3 बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी, 2015 को **पानीपत (हरियाणा)** में **'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ'** योजना की शुरुआत की। इस योजना को पहले चरण में देश के **100 जिलों** में चलाया जा रहा है।
- इसके लिए **रु. 100 करोड़** का आरंभिक बजट रखा गया है। फिल्म अभिनेत्री **'माधुरी दीक्षित'** को इस योजना का **'ब्रैण्ड एम्बेसडर'** बनाया गया है।
- **कन्या जन्म** को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न राज्यों में पूर्व से चलाई जा रही कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं निम्न हैं
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (बिहार)
- सुकन्या योजना (महाराष्ट्र)
- नन्दा देवी कन्या योजना (उत्तराखण्ड)
- कन्या विद्या धन योजना (उत्तर प्रदेश)

4 सुकन्या समृद्धि योजना

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी, 2015 को बालिकाओं के लिए लघु बचत स्कीम के तहत **'सुकन्या समृद्धि योजना'** की शुरुआत **पानीपत (हरियाणा)** में की।
- यह योजना **'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'** अभियान का हिस्सा है।
- सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य बालिकाओं के प्रति **परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन** तथा उसके नाम से बचत को प्रोत्साहन प्रदान करना है।
- इसके तहत **10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं** के लिए बैंक खाता खोला जाना है।

5 पण्डित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन योजना

- कुशल शिक्षकों को तैयार करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25 दिसम्बर, 2014 को वाराणसी से 'पण्डित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन योजना' की शुरुआत की।
- इसके लिए 10वीं तथा 12वीं के स्तर पर 'शिक्षक प्रशिक्षण' के कोर्स को स्थान दिया जाएगा।

6 मिशन इन्द्रधनुष

- केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसम्बर, 2014 को मिशन इन्द्रधनुष प्रारंभ किया।
- इसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक सम्पूर्ण टीकाकरण के कार्य को पूरा करना है।
- इसके अन्तर्गत सभी बच्चों को सात वैक्सीन दी जानी है जिनसे उन्हें डिप्थीरिया, कूकर खांसी, टिटनेस, पोलियो, क्षयरोग मिजेल्स तथा हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों से बचाव की प्रतिरोधक क्षमता दी जा सके।
- 'मिशन इन्द्रधनुष' की शुरुआत सुशासन दिवस (गुड गवर्नेन्स डे) के अवसर पर की गई।

7 स्वच्छ भारत मिशन

- 15 अगस्त, 2014 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम अपने उदबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा था- हम तय करें कि वर्ष 2019 में जब हम महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मनाएंगे तो हमारा गांव, हमारा शहर, हमारी गली, हमारा मोहल्ला, हमारे स्कूल हमारे अस्पताल सभी क्षेत्रों में हम गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे।
- स्वच्छ भारत मिशन की अवधि 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक होगी।
- प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली स्थित वाल्मीकि बस्ती से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की।
- गुजरात के राजकोट जिले की सुश्री भाग्यश्री सेठ द्वारा प्रेषित नारा 'एक कदम स्वच्छता की ओर' का चयन किया गया।

8 अटल पेंशन योजना

- एक हजार, दो हजार, तीन हजार, चार हजार तथा पांच हजार रुपए मासिक पेंशन का विकल्प।
- 18 से 40 वर्ष की उम्र में एक ऐसे बैंक खाताधारक जिसकी आय कर योग्य नहीं है और जो किसी अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं, इसके पात्र हैं। 60 वर्ष की उम्र से मिलना शुरू होगी पेंशन।
- 31 दिसंबर, 2015 से पहले योजना में शामिल होने वालों के लिए सरकार हर साल अधिकतम रु. 1000 का योगदान अपनी ओर से देगी।

9 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

- दुर्घटना के कारण मृत्यु पर बीमा राशि रु. 2 लाख।
- दुर्घटना में दोनों आंखों की दृष्टि पूरी तरह चली जाने और उनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं होने, दोनों हाथों या दोनों पैरों के इस्तेमाल लायक न रहने पर बीमा राशि रु. 2 लाख।
- एक आंख की रोशनी पूरी तरह चले जाने और उसके वापस आने की कोई संभावना नहीं होने या एक हाथ या पैर इस्तेमाल लायक नहीं रहने पर रु. 1 लाख की बीमा राशि।
- 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के हर बैंक खाताधारक इसके लिए पात्र हैं आधार होगा मुख्य केवाईसी।
- सालाना प्रीमियम राशि केवल रु. 12।

10 मेक इन इंडिया

- प्रधानमंत्री ने 25 सितंबर, 2014 को नई दिल्ली में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा की।
- इसी कार्यक्रम में मेक इन इंडिया के लोगो शेर का अनावरण किया गया।
- 100 करोड़ रुपये की पूंजी से राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।
- प्राधिकरण का मुख्यालय पुणे (महाराष्ट्र) में होगा।

11 राष्ट्रीय बाल स्वच्छता मिशन

- 14 नवंबर, 2014 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने राष्ट्रीय बाल सदस्यता मिशन प्रारंभ किया। यह अक्टूबर, 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ किए गए स्वच्छ भारत मिशन का ही एक हिस्सा है।

12 किसान विकास पत्र

- नवंबर, 2014 में केंद्र सरकार ने देश में बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किसान विकास पत्र को पुनः लांच किया है।
- सरकार द्वारा यह निर्णय पिछले दो तीन वर्षों में देश की बचत दर गिरने के कारण लिया गया है।

13 पहल योजना

- देश में रसोई गैस के 60 फसीदी से अधिक ग्राहक महत्वाकांक्षी पहल योजना में शामिल हो गए जिससे नकद सब्सिडी प्राप्त कर वे बाजार मूल्य पर रसोई गैस (एलपीजी) खरीद सकते हैं। 15.33 करोड़ में से 9 करोड से अधिक उपभोक्ता प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण योजना (DBTL) में शामिल हो गए हैं और उन्हें नकद 2,262 करोड़ रुपए स्थानांतरित कर दिया गया है।

14 सुकन्या समृद्धि लेखा

- प्रतिवर्ष (2014-15) 9.1% के ब्याज दर, गणना वार्षिक आधार पर
- एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 1000/- और अधिकतम भारतीय रुपये 1,50,000/- 100 रुपये के गुणक का आवर्ती जमा जो एकमुश्त भी जमा कराया जा सकता है।
- 21 वर्ष पूरे होने के बाद खाता बंद कर दिया जा सकता है।

15 अमृत महोत्सव

- वर्ष 2022 आजादी के 75 साल ''टीम इंडिया'' के लिए विजन, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में।
  - (i) 24x7 बिजली की बुनियादी सुविधा, स्वच्छ पेयजल, एक शौचालय और सड़क संपर्क।
  - (ii) सभी के लिए आवास- शहरी क्षेत्रों में 2 करोड़ घरों और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 करोड़ घरों का निर्माण।
  - (iii) कम से कम एक सदस्य की आजीविका के लिए साधन तक पहुंच हो।
  - (iv) गरीबी में पर्याप्त कमी।
  - (v) ऑफ-ग्रिड सहित सौर पावर उपयोग करने वाले 20,000 गांवों का 2020 तक विद्युतीकरण।

16 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

- सरकार ने 43,033 करोड़ रुपये के ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को मंजूरी दी।

नोट: स्कीम मौजूदा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) का स्थान लेगी।

17 केंद्र सरकार का राष्ट्रव्यापी बाल स्वच्छता मिशन

1. स्वच्छ आंगनबाड़ी
2. आसपास के परिवेश, खेल के मैदानों की तरह स्वच्छ
3. व्यक्तिगत स्वच्छता (व्यक्तिगत स्वच्छता/बाल स्वास्थ्य)
4. स्वच्छ भोजन
5. स्वच्छ पेयजल
6. स्वच्छ शौचालय

लोगो : कोल्हापुर के श्री अनंत खास्बरदार द्वारा बनाया गया है। महाराष्ट्र राज्य लोगो डिजाइन प्रतियोगिता में जीता।

- टैगलाइन 'एक कदम स्वच्छता की ओर' राजकोट, गुजरात के भाग्यश्री सेठ द्वारा दिया गया।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एंबेसडर के रूप में बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को नियुक्त किया।

18 'ज्ञान' योजना का शुभारंभ

- केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति इरानी ने आईआईटी गांधीनगर, गुजरात में ज्ञान (ग्लोबल इनिशियेटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स) योजना का शुभारम्भ किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है।

19 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

- सभी नागरिकों के लिए सेवानिवृत्ति आय प्रदान करने के उद्देश्य के साथ 1 जनवरी, 2004 को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) शुरू किया गया था।

20 सुगम्य भारत अभियान

- केन्द्र सरकार की ओर से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नि:शक्तजनों के लिए सुगम्य भारत अभियान की शुरूआत की है। नि:शक्तजनों के लिए सार्वभौमिक सुगम्यता लक्ष्य हासिल करने के लिए सुगम्य भरत अभियान प्रारंभ किया गया है।

21 उदय योजना 2015

- 5 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। उदय योजना का लक्ष्य बिजली वितरण कंपनियों का वित्तीय सुधार करना और उनका पुनरुद्धार करना है।

22 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

- 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को वर्तमान में संचालित योजनाओं यथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, भूमि संसाधन विभाग के समेकित वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम तथा कृषि एवं सहकारिता विभाग के राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन के खेत पर जल प्रबंधन घटक का एकीकरण से विकसित किया गया है।

23 सुगम्य भारत योजना

- 3 दिसंबर 2015 को विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी तथा राज्यों की राजधानियों के सभी सरकारी भवनों के न्यूनतम 50 प्रतिशत तक को जुलाई 2019 तक नि:शक्त जनों के लिए सुगम्य बना दिया जाएगा।

24 स्मार्ट सिटी मिशन

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को तीन नए शहरी मिशनों की घोषणा की। सबसे ज्यादा स्मार्ट शहर (13) उत्तर प्रदेश तथा दूसरे क्रम पर (12) तमिलनाडु को प्राप्त हुए हैं। इस मिशन को केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में चलाया जाएगा।

25 इन्द्र धनुष मिशन

- इस मिशन की शुरुआत 16 अगस्त, 2015 को वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा की गई। इस मिशन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए सात-सूत्री अभियान को आरंभ किया गया है।

26 मुद्रा बैंक योजना

- इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अगस्त, 2015 को की गई थी। इसमें शिशु, किशोर तथा तरुण योजनाओं के तहत क्रमश: 50 हजार रुपये से 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है।

27 प्रधामंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

- 9 जून, 2016 से प्रारम्भ की गई इस योजना का उद्देश्य सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देना है। इस अभियान के तहत प्रत्येक माह की नौ तारीख को प्रत्येक जिला चिकित्सालय में लगने वाले विशेष कैंप में महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व की जानकारी दी जाएगी।

28 प्रधामंत्री ग्रामीण आवास योजना

- इस योजना को केंद्रीय कैबिनेट ने 23 मार्च, 2016 को स्वीकृति प्रदान की। यह योजना दिल्ली एवं चण्डीगढ़ को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू की गई है। इसके तहत मैदानी क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
- **सबके लिए आवास योजना :** केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'सबके लिए आवास' हेतु 29 अगस्त, 2015 को नौ राज्यों के 305 शहरों का चयन किया गया। इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के लिए 2 करोड़ आवासों का निर्माण किया जाना है।

29 भारतम् परियोजना

- 4 अप्रैल, 2016 में प्रारंभ इस परियोजना का उद्देश्य देश के सभी राजमार्गों को वर्ष 2019 तक रेलवे क्रॉसिंग मुक्त करना है। इसके लिए 102 अरब रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

30 श्याम प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन

- यह योजना 21 फरवरी, 2016 को आरंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत स्मार्ट गाँव विकसित किए जाएंगे। इसके तहत गाँवों के आर्थिक विकास, रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा ग्रामीण शहरी अन्तर को मिटाने जैसे कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

31 सांसद आदर्श ग्राम योजना

- इस योजना की शुरुआत 11अक्टूबर, 2014 को की गई। यह 'ग्राम स्वराज' की अवधारणा पर आधारित कार्यक्रम है। इसके तहत प्रत्येक सांसद को वर्ष 2019 तक तीन गाँवों को विकसित करना है। इसका उद्देश्य भारत के गाँवों का भौतिक और संस्थागत ढांचे का सम्पूर्ण विकास करना है।

32 स्टार्टअप इण्डिया/स्टैण्ड अप

- प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2015 को लाल किले की प्राचीर से इस योजना को आरंभ करने की घोषणा की। भारतीय युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए इन योजनाओं को प्रारंभ किया जाएगा। स्टैण्डअप योजना के तहत बैंकों के द्वारा एससी/एसटी तथा महिला उद्यमियों को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के लोन दिए जाएँगे। स्टार्टअप योजना के तहत नए उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की छूट तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

33 मेरा जिला मेरी योजना

- पूर्ण साक्षरता हासिल करने की दिशा में शिक्षा मिशन एवं जन शिक्षण संस्था की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य निरक्षर लोगों को साक्षर बनाना है।

34 दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना

- 17 अक्टूबर, 2014 को जारी इस योजना का उद्देश्य श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल योजनाएँ बनाना है। इसके तहत श्रम निरीक्षण, एकीकृत भविष्यनिधि खाता नंबर तथा श्रम मंत्रालय में एकल खिड़की निष्पादन जैसी योजनाएँ शामिल हैं।

35 स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना

- इस योजना की शुरुआत 14 नवंबर, 2015 को की गई थी। तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्द्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन के तहत इन योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पर्यटन स्थलों पर विश्वस्तरीय सुविधाएँ विकसित कर पर्यटन को बढ़ावा देना है।

36 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

- 15 जुलाई, 2015 में प्रारंभ की गई इस योजना के तहत युवाओं में कौशल विकसित किए जा रहे हैं। इसके तहत देशभर के 24 लाख युवाओं को विभिन्न उद्योगों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके तहत **10 करोड़** नए तथा 30 करोड़ वर्तमान श्रम बल को कुशल बनाया जाएगा।

37 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना

- इस योजना की शुरुआत 25 सितंबर, 2014 को की गई थी। यह योजना ग्रामीण जगत के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लक्षित है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 35 वर्ष की आयु के ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएँगे।

38 उस्ताद योजना

- इस योजना की शुरुआत 14 मई, 2014 को वाराणसी में की गई। उस्ताद योजना (अपग्रेडिंग द स्किल्स एण्ड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स/क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट) को अल्पसंख्यकों की पारम्परिक कला/शिल्प की समृद्ध विरासत के संरक्षण और परम्परागत कारीगरों की क्षमता निर्माण हेतु शुरू किया गया है।

39 उजाला योजना

- यह योजना **11 मार्च, 2016** को भारत सरकार ने लागू की। उजाला योजना ऊर्जा सहायता सेवा लिमिटेड द्वारा लागू किए जा रहे 'सभी के लिए रियायती एलईडी से उन्नत ज्योति' कार्यक्रम का संक्षिप्त नाम है।

40 स्वर्ण भारत योजना

- यह योजना 5 नवंबर, 2015 को आरंभ की गई। सोने के आयात को नियंत्रित करना तथा घरेलू संग्रह की उपयोगिता बढ़ाना। इस योजना में गोल्ड मोनेटाइजेशन, गोल्ड बॉण्ड स्कीम तथा इंडियन गोल्ड क्वाइन को शामिल किया गया है।

41 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

- इस योजना को 19 फरवरी, 2015 को आरंभ किया गया। इस योजना के तहत कृषकों को एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाएगा। इस कार्ड पर मृदा की गुणवत्ता, अपेक्षित उर्वरक आदि की मात्रा प्रयोगशाला परीक्षणों की रिपोर्ट पर दर्ज होगी।

42 राष्ट्रीय गोकुल मिशन

- इस मिशन की शुरुआत 28 जुलाई, 2014 को की गई थी। यह मिशन स्वदेशी गायों के संरक्षण से संबंधित है। यह मिशन पशु प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम पर आधारित है।

43 डिजिटल लॉकर योजना

- केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद तथा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने **7 अगस्त, 2016** को महत्वाकांक्षी 'डिजिटल लॉकर' योजना की शुरुआत की। **इसे 'डिजी लॉकर'** नाम से भी जाना जा रहा है। **डिजिटल लॉकर** योजना में सभी प्रकार के दस्तावेजों को एक एप्लीकेशन में अपलोड करना होगा। वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस तथा रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र को साथ में रखने की जरूरत नहीं होगी। एप्प में सभी प्रकार के दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी मौजूद होगी। एप्प की सहायता से दस्तावेजों को देखा जा सकता है। यह नि:शुल्क उपलब्ध होगा।